UPSC-CSE 2027/28
DAILY
CURRENT AFFAIRS
ONE STOP SOLUTION
By Faiyaz Sir
The Indian EXPRESS
THE HINDU
pib
PRESS INFORMATION BUREAU
22
SEPTEMBER
COMPLETE COVERAGE
EXAM FOCUSED
ANALYSIS MADE EASY
STATIC + CURRENT INTEGRATION
STAY AHEAD
STAY PREPARED

Dream
Plan
Study
Achieve
अपनी क्षमताओं पर
संदेह करने के बजाय,
अपने लक्ष्यों को हासिल करने पर
ध्यान केंद्रित करें।
DISCIPLINE
FOCUS
HARD WORK
RESULTS
UPSC
IAS
PCS
SUCCESS
Small
Steps
Big
Goals
Better Plan
More Focus
Bigger Dreams
Success

आज क्या पढ़ेंगे?

- **India-New Zealand FTA**
- **Arrest and Detention**
- **महत्वपूर्ण तथ्य**

India-New Zealand FTA takes effect on Oct. 20

- The agreement aims at doubling bilateral trade to ₹35,000 crore over the 'next four to five years'
- India's dairy, and other sensitive agriculture sectors will remain protected, says Minister
- FTA to erase import levies on Indian goods; 95% exports to India to be tariff-free or at low levies

Saptaparno Ghosh
NEW DELHI

The Free Trade Agreement (FTA) between India and New Zealand that was ratified on Monday and comes into effect on October 20 aims at doubling bilateral trade to ₹35,000 crore in the "next four to five years", according to Union Commerce Minister Piyush Goyal.

"The entry into force of the India-New Zealand FTA will translate this goal into concrete economic outcomes," he told journalists.

According to New Zealand's foreign trade office, the FTA is set to erase import levies on all Indian goods, while 95% of exports to India will either be allowed tariff-free or at "sharply" reduced levies.

Mr. Goyal insisted that India has safeguarded its sensitive sectors, such as dairy and agricultural produce, including onions, almonds, chickpeas, peas, artificial honey, and sugar, not granting Wellington any relaxation or concessions on these products in the agreement. The deal will benefit India's micro, medium, and small enterprises, farmers, handloom artisans, and weavers, the Minister added.

New Zealand also has technological expertise in manufacturing of engineering and other goods, Mr. Goyal said. "They could look to support our companies or invest and set up manufacturing in India to capture global markets," he added.

They [New Zealand] could look to support our companies or invest and set up manufacturing in India to capture global markets

PIYUSH GOYAL
Union Commerce Minister

It [the FTA] gives confidence to our business communities to grow, form relationships, and trade

TODD McCLAY
Minister of Trade and Investment, New Zealand

New Zealand's Minister of Trade and Investment, Todd McClay, emphasised the significance of the two countries getting the deal done at a time of global "uncertainty", with escalating tariffs and trade barriers. "It gives confidence to our business communities to grow, form relationships, and trade," he said.

India is New Zealand's ninth largest export market, and the value of bilateral trade between the two countries stood at $1.3 billion in the fiscal year 2024-25.

Elaborating on the potential avenues for investment, Mr. Goyal said: "There are many areas where they have cutting-edge technology and innovation. Agriculture is one of their strengths in certain products." He pointed to kiwi farming and apiculture as prime examples.

Wellington has committed $20 billion worth of foreign direct investment into India as part of the deal.

The Commerce Minister said that global investors are interested in setting up manufacturing in India not only for access to the large Indian market but also to help "seamlessly export" to about two-thirds of the global economy where India has preferential market access.

Mr. Goyal observed that in several countries, including New Zealand, labour is scarce and expensive. Manufacturing in India instead would be more economical.

U.S. sanctions law

"They are on the lookout for countries where they can export their technology to a trusted partner, where intellectual property is respected and would not be stolen," he added.

Asked about India's response to recent United States legislation imposing sanctions on countries buying Russian oil, Mr. Goyal said that the fine print of the law was being studied.

Responding to a query from *The Hindu* about progress on India's trade deal with Chile, Mr. Goyal said, following productive talks, "in the coming months, we will hear some good news."

About the trade deal with Canada, the Union Minister noted that both sides have resolved to fast-track discussions. Indian negotiators are slated to visit the North American country for the fifth round of talks on October 5, he said.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - FTA)

- **लागू होने की तिथि:** भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह समझौता (FTA) **20 अक्टूबर** से लागू होने जा रहा है।
- **व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य:** केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, अगले 4 से 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके **₹35,000 करोड़** तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **भारतीय संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा:** डेयरी (Dairy) और संवेदनशील कृषि उत्पाद (जैसे - प्याज, बादाम, चना, मटर, कृत्रिम शहद, चीनी) को इसमें विशेष छूट या रियायत नहीं दी गई है ताकि भारतीय किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों की सुरक्षा बनी रहे।

शुल्क में राहत (Tariff Cuts):

- न्यूजीलैंड में भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।
- न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% निर्यात पर भी टैरिफ-फ्री (शुल्क-मुक्त) या बहुत कम शुल्क लागू होगा।
- **निवेश और तकनीक:** न्यूजीलैंड ने भारत में $20 बिलियन (डॉलर) के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही, न्यूजीलैंड की कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेट-अप करने और उन्नत तकनीकों (जैसे - कीवी फार्मिंग और मधुमक्खी पालन/Apiculture) को साझा करने में रुचि रख रही हैं।

1. भारत को क्या फायदा होगा? (Benefits for India)

- **100% भारतीय सामानों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस:** भारत से न्यूज़ीलैंड निर्यात होने वाले **सभी (100%) उत्पादों** पर अब कोई आयात शुल्क (Import Duty) नहीं लगेगा। इससे भारत के **टेक्सटाइल (कपड़ा), चमड़ा (Leather), रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प और MSME उद्योगों** को बड़ा फायदा होगा।
- **सस्ते कच्चे माल की आपूर्ति:** भारत की विनिर्माण (Manufacturing) इकाइयों के लिए लकड़ी (Wooden logs), ऊन (Wool), सी-कोकिंग कोल (Coking Coal) और स्क्रैप मेटल जैसी चीजें बिना शुल्क या कम टैरिफ पर मिलेंगी, जिससे भारतीय सामानों की उत्पादन लागत कम होगी।
- **कुशल श्रमिकों के लिए वीजा (Skilled Visa Pathway):** न्यूज़ीलैंड ने 5,000 योग्य भारतीय कुशल श्रमिकों (Skilled Workers) के लिए अस्थायी रोजगार वीजा (Temporary Employment Entry) का कोटा तय किया है।
- **भारतीय छात्रों को लाभ:** न्यूज़ीलैंड में पढ़ने वाले भारतीय छात्र पढ़ाई के साथ हफ्ते में कम से कम 20 घंटे काम कर सकेंगे। इसके अलावा, पढ़ाई पूरी होने के बाद पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा (Post-Study Work Visa) का प्रावधान किया गया है।
- **सेवा क्षेत्र (Services Sector) और AYUSH:** योग शिक्षकों, भारतीय रसोइयों (Chefs), संगीत शिक्षकों, आईटी पेशेवरों, स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा (आयुष/AYUSH) सेवाओं के लिए न्यूज़ीलैंड का बाजार सुलभ होगा।
- **भारी निवेश:** न्यूज़ीलैंड भारत में अगले कुछ वर्षों में **$20 बिलियन (डॉलर)** का सीधा विदेशी निवेश (FDI) करेगा।

2. न्यूजीलैंड को क्या फायदा होगा? (Benefits for New Zealand)

- **विशाल भारतीय बाजार तक पहुंच:** न्यूजीलैंड के **95% निर्यात** को भारत में या तो बिना शुल्क (Tariff-free) या बेहद कम टैरिफ पर एंट्री मिलेगी।
- **प्रमुख निर्यात क्षेत्र:** न्यूजीलैंड की भेड़ का मांस (Sheep meat), लकड़ी, ऊन, कच्चा चमड़ा, पेट्रोकेमिकल्स और कुछ इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल मशीनरी पर भारतीय सीमा शुल्क तुरंत या चरणबद्ध तरीके से खत्म/कम हो जाएगा।
- **कोटा प्रणाली के तहत कुछ कृषि उत्पाद:** न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध फल जैसे **कीवी (Kiwifruit), सेब (Apples), और मानुका शहद (Manuka Honey)** के लिए भारत ने टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत सीमित प्रवेश की अनुमति दी है।
- **भारत में मैन्युफैक्चरिंग/कृषि तकनीक साझा करना:** न्यूजीलैंड अपनी आधुनिक कृषि पद्धतियों (जैसे कीवी फार्मिंग और मधुमक्खी पालन/Apiculture) की तकनीक भारत के साथ साझा करेगा और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इस्तेमाल कर सकेगा।

3. भारत ने किन उत्पादों को छूट/पहुंच (Access) नहीं दी है?

- भारत ने अपने घरेलू किसानों, डेयरी उद्योग और स्थानीय एमएसएमई की सुरक्षा के लिए **लगभग 30% टैरिफ लाइनों (लगभग 29.97%)** को इस समझौते से पूरी तरह **बाहर (Exclusion List में)** रखा है। इन पर न्यूज़ीलैंड को कोई टैरिफ छूट नहीं मिलेगी:
- **डेयरी उत्पाद (Dairy Sector):** दूध, क्रीम, मक्खन, पनीर (Cheese), दही, म्ठा (Whey) और अन्य डेयरी उत्पाद पूरी तरह प्रतिबंधित/संरक्षित रखे गए हैं।
- **संवेदनशील कृषि व सब्जी उत्पाद:**
  - प्याज (Onions)
  - चना (Chana/Chickpeas) और मटर (Peas)
  - मक्का (Corn) और बादाम (Almonds)
  - चीनी (Sugar) और कृत्रिम शहद (Artificial Honey)
- **वसा एवं तेल:** पशु, वनस्पति और माइक्रोबियल वसा एवं तेल (Fats and Oils)।
- **अन्य प्रमुख क्षेत्र:**
  - हथियार और गोला-बारूद (Arms and Ammunition)
  - कॉपर (तांबा) और एल्युमीनियम की कुछ वस्तुएं
  - रत्न एवं आभूषण (Gems and Jewellery)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास प्रश्न

- **प्रश्न 1. भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. इस समझौते के तहत न्यूज़ीलैंड को भारतीय डेयरी क्षेत्र में शत-प्रतिशत (100%) शुल्क-मुक्त प्रवेश (duty-free access) मिला है।
2. इस समझौते का उद्देश्य अगले 4 से 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके ₹35,000 करोड़ तक पहुँचाना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न

- *"अपरिमित संभावनाओं के बावजूद, भारत को मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में अपने संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ स्वदेशी उद्योगों के हितों का संतुलन बनाना पड़ता है।"* भारत-न्यूज़ीलैंड FTA के विशेष संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द / 15 अंक)

Accused entitled to release if grounds of arrest not given: SC

Right to know grounds of arrest, availability of counsel of choice are fundamental rights under Article 22(1) of Constitution, and 'cannot be breached under any situation', says Supreme Court

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court in a judgment on Monday held that an arrested person kept in the dark about the grounds of arrest and without access to a lawyer was entitled to immediate release.

The right to know the grounds of arrest in writing in a familiar language, and the availability of a counsel of choice, was a sacrosanct fundamental right under Article 22(1) of the Constitution, and "cannot be breached under any situation", a Bench headed by Justice Ujjal Bhuyan said. It has to be followed without exception and at the earliest.

"Any breach or non-compliance would entail immediate release of the arrested person because such arrest is unconstitutional. We cannot tinker with the most important safeguards provided under Article 22... Any attempt to encroach upon the fundamental rights guaranteed under Article 22(1) of the Constitution has to be frowned upon by the courts and dealt with strictly. It would vitiate the process of arrest and remand," Justice Bhuyan observed.

> Any attempt to encroach upon the fundamental rights guaranteed under Article 22(1) of the Constitution has to be frowned upon by the courts and dealt with strictly. It would vitiate the process of arrest and remand
>
> JUSTICE UJJAL BHUYAN
> Supreme Court judge

The Bench, also comprising Justice Atul S. Chandurkar, said the right under Article 22(1) was a "mandatory constitutional safeguard". It applied across the spectrum, including offences under the Indian Penal Code and under special enactments, which include the laws on terrorism and money laundering.

Probe agencies cannot shrug off a breach of Article 22(1) as a "mere procedural lapse", Justice Bhuyan observed. Agencies cannot contend that a violation of the Article would not render custody illegal or entitle an accused to bail. The agencies had it completely wrong, the Bench said.

"When an accused is released for violation of his fundamental rights under Article 22(1), he is not enlarged on bail. He is released from illegal and unconstitutional detention," Justice Bhuyan emphasised.

Even subsequent filing of chargesheet and order of cognisance would not validate such an arrest, Justice Bhuyan underscored.

No blanket immunity

The court was answering a question as to whether an accused who had suffered breach of Clauses (1) and (2) of Article 22 could be re-arrested for the same offence, and if so, under what circumstances. Clause (2) of the Article mandates the production of an accused person before the Magistrate within 24 hours of arrest.

There cannot be a blanket immunity against future arrest, Justice Bhuyan said, as some cases relate to grave offences. However, any such move by the probe agencies must be based on stringent judicial oversight in order to protect citizens from police arbitrariness.

The apex court directed that a specific sanction from the Magistrate concerned must precede any attempt by the police to arrest for the second time a person whose earlier arrest was declared illegal for violating rights under Article 22(1) of the Constitution.

The police must apply before the Magistrate, providing recorded reasons for seeking arrest, the judgment said.

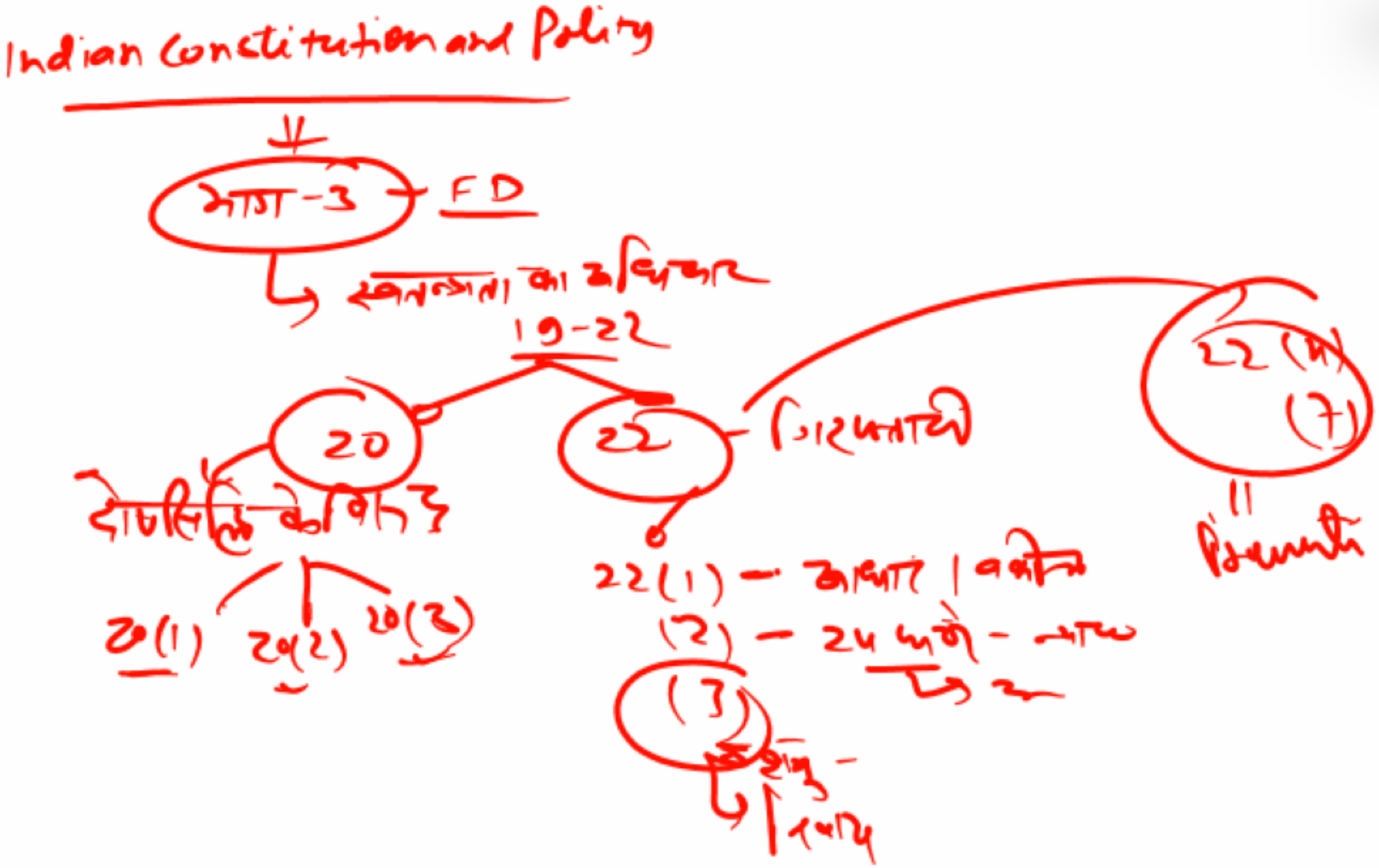

संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

1. मुख्य निर्णय

- **तुरंत रिहाई का अधिकार:** यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी **गिरफ्तारी का कारण (Grounds of Arrest)** लिखित में और उसकी समझ में आने वाली भाषा में नहीं बताया जाता है, या उसे **अपनी पसंद के वकील (Counsel of choice)** से संपर्क नहीं करने दिया जाता है, तो वह व्यक्ति तुरंत रिहाई (Immediate Release) का हकदार है।
- **अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारणों को जानना और वकील का अधिकार संविधान के **अनुच्छेद 22(1) के तहत पवित्र और अनिवार्य मौलिक अधिकार (Mandatory Constitutional Safeguard)** हैं, जिनका किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

2. फैसले की प्रमुख बातें

- **सख्त कानूनी प्रक्रिया:** पीठ (Bench) की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस उज्ज्वल भुयान (Justice Ujjal Bhuyan) और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर ने स्पष्ट किया कि इसका पालन बिना किसी अपवाद के और जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।
- **विशेष और कड़े कानूनों पर भी लागू:** यह नियम केवल सामान्य अपराधों (IPC) पर ही नहीं, बल्कि **आतंकवाद (Anti-Terror Laws)** और **मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering - PMLA)** जैसे कड़े विशेष कानूनों के तहत दर्ज मामलों पर भी समान रूप से लागू होता है।
- **प्रक्रियात्मक चूक (Procedural Lapse) नहीं:** जांच एजेंसियां (जैसे CBI, ED, पुलिस) इसे केवल "प्रक्रियात्मक चूक" बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकतीं। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पूरी गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड की प्रक्रिया ही अवैध (Unconstitutional/Vitiated) मान ली जाएगी।
- **चार्जशीट से अवैधता खत्म नहीं होगी:** सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि बाद में चार्जशीट दाखिल कर देने या संज्ञान (Cognizance) ले लेने से भी शुरुआती अवैध गिरफ्तारी वैध नहीं ठहराई जा सकती।

3. दोबारा गिरफ्तारी (Re-arrest) पर कड़े नियम

- **कवर-ऑल इम्युनिटी नहीं:** कोर्ट ने माना कि गंभीर अपराधों के मामलों में जांच एजेंसियों को भविष्य की गिरफ्तारी से पूरी तरह छूट नहीं दी जा सकती, लेकिन पुलिस अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती।
- **मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य:** यदि किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के कारण रिहा किया गया है और पुलिस उसे उसी अपराध में दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है, तो उसे पहले **संबंधित मजिस्ट्रेट से विशेष मंजूरी (Specific Sanction)** लेनी होगी। इसके लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने लिखित में ठोस कारण दर्ज कराने होंगे।

- **प्रश्न . हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर दिए गए फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. यदि किसी अभियुक्त को गिरफ्तारी के लिखित आधार (Grounds of Arrest) प्रदान नहीं किए जाते हैं, तो उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की पूरी प्रक्रिया अवैध हो जाती है।
2. मामले में बाद में चार्जशीट (Chargesheet) दाखिल कर देने से शुरुआती अवैध गिरफ्तारी स्वतः वैध हो जाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न

- *"अनुच्छेद 22(1) के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक संरक्षण किसी भी स्थिति में उल्लंघन योग्य नहीं हैं।"* उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णयों के आलोक में परीक्षण कीजिए कि यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) और पुलिस की मनमानी शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने में किस प्रकार सहायक है। (250 शब्द / 15 अंक)

महत्वपूर्ण तथ्य

100% drought likely to be declared in Maharashtra by month-end: Minister

Never seen such severe dry spell, says Cooperation Minister Babasaheb Patil; State has initiated student fee waivers, electricity bill reductions and water tanker deployments in response, he adds

The Hindu Bureau
MUMBAI

Maharashtra Cooperation Minister Babasaheb Patil on Monday said the BJP-led Mahayuti government will soon declare 100% drought in the State. Speaking on the severity of the crisis, Mr. Patil said, "In my entire life, I have never seen such a severe drought. All crops, including soya bean, cotton and sugarcane, have suffered due to the dry spell and the loss is huge. The 100% drought declaration is expected by the end of September based on the National Disaster Response Fund norms."

The Minister said the government has already initiated measures such as fee waiver for students, electricity bill waiver, and deployment of water tankers to provide relief.

The statement assumes significance as it is the first time a Minister has spoken of a 100% drought declaration. So far, the official position of the government has been that crop damage surveys and ground verification would be conducted after October 5.

A farmer in Umarga taluka of Dharashiv district letting his cattle graze on his crop that has withered due to the dry spell. SPECIAL ARRANGEMENT

Several regions in the State have been facing a prolonged dry spell, causing extensive crop loss and forcing farmers to incur heavy losses. According to the State Agriculture Department, rainfall has remained absent for over 20 days in at least 83 talukas across 20 districts. At least six districts, including Amravati, Solapur and Latur, have recorded rainfall deficit of 40-50%. Water tankers have started plying in villages such as Naichakur in Dharashiv district.

Advisory to districts

In view of the crisis, the State government has instructed district administrations to revive existing water sources and build water supply networks in villages facing shortage instead of treating tankers as the first solution.

A circular issued by the State Soil and Water Conservation Department on September 16 stated that the Groundwater Surveys and Development Agency will identify villages with drinking water shortage and submit the list to District Collectorates by October. District Collectors will have to plan interventions for the villages for the period between October and December. The plans are to be submitted by November 15, followed by plans for January-March 2027 by December 20, and for April-June 2027 by January 20, it stated.

Meanwhile, Chief Minister Devendra Fadnavis on Monday said the government would not wait for Central assistance to help farmers facing distress due to inadequate rainfall. "A formal crop loss assessment would be carried out after October 5 as required under the rules, following which the State would seek assistance from the Centre," he told reporters.

YouTube Homework

- Scheduled Natural Calamities

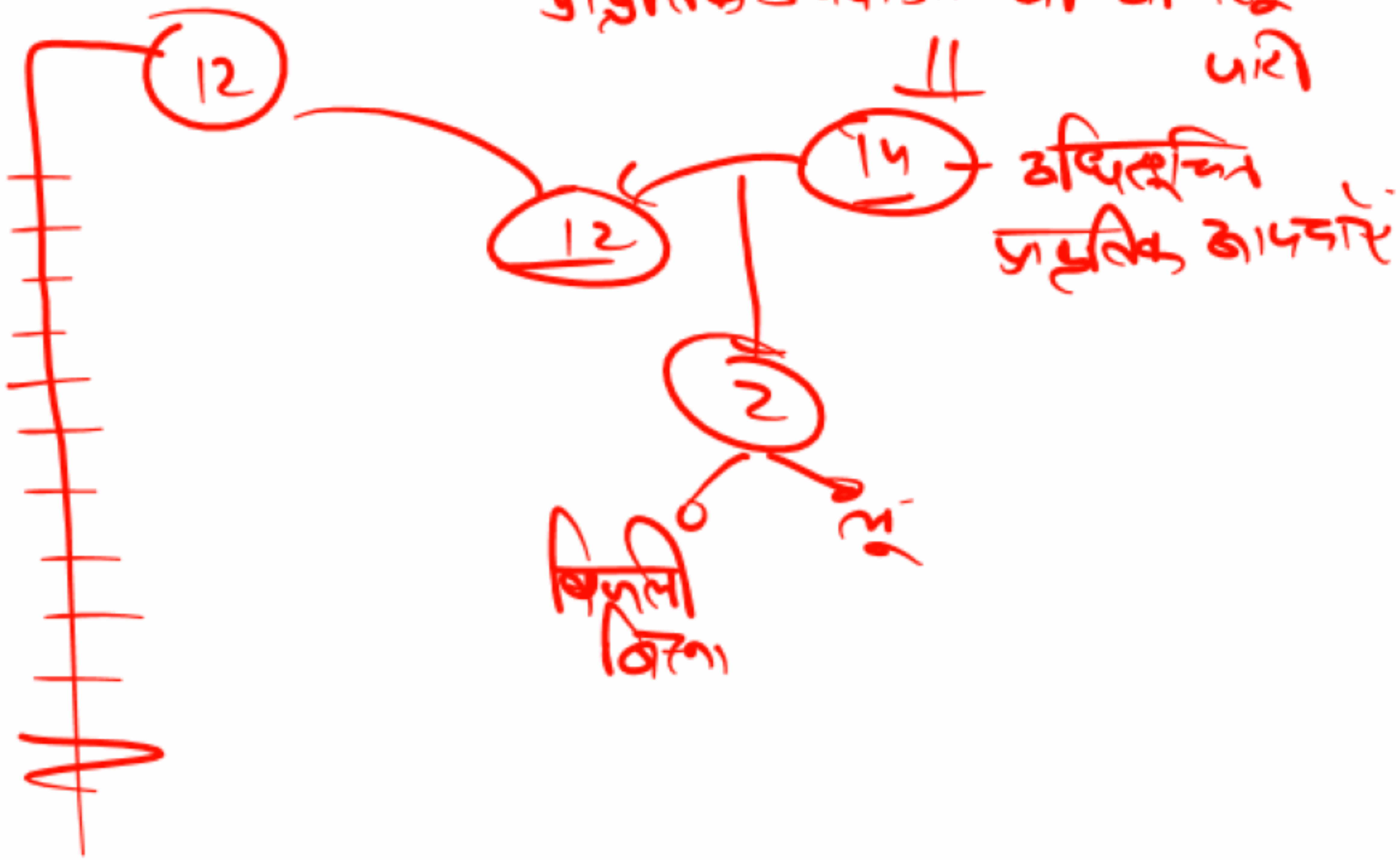

महत्वपूर्ण तथ्य

- **सूखा (Drought) क्या है, इसे कैसे घोषित किया जाता है और इससे किसानों को क्या लाभ मिलते हैं:**

1. सूखा (Drought) क्या है?

- सूखा एक ऐसी स्थिति है जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक **पर्याप्त वर्षा नहीं होती**, जिससे जल संसाधनों की भारी कमी हो जाती है। इसके कारण खेती, पेयजल, भूजल और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है।

सूखे के मुख्य प्रकार:

- **मौसम संबंधी सूखा (Meteorological Drought):** जब सामान्य से बहुत कम वर्षा होती है।
- **कृषि संबंधी सूखा (Agricultural Drought):** जब मिट्टी में नमी की इतनी कमी हो जाती है कि फसलें सूखने लगती हैं।
- **जलवैज्ञानिक सूखा (Hydrological Drought):** जब नदियों, झीलों, बांधों और भूजल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है।

2. सूखा कैसे घोषित किया जाता है? (समीक्षा व प्रक्रिया)

- भारत में सूखा घोषित करने का अधिकार **राज्य सरकार (State Government)** के पास होता है। इसके लिए **'मैनुअल फॉर सूखा प्रबंधन (2016)'** के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है:
- **प्राथमिक मानदंड (Primary Indicators):**
  - **वर्षा की कमी:** मानसून सीजन (जून से सितंबर) के दौरान सामान्य से 20% या उससे अधिक वर्षा की कमी होना।
  - **शुष्क अवधि (Dry Spells):** मानसून के दौरान लगातार 3 से 4 सप्ताह तक वर्षा न होना।
- **द्वितीयक मानदंड (Secondary Indicators):**
  - **फसल बुवाई क्षेत्र:** सामान्य क्षेत्र की तुलना में फसल की बुवाई में कमी।
  - **वनस्पति सूचकांक (NDVI):** सैटेलाइट डेटा के जरिए फसलों और हरियाली के स्वास्थ्य की जांच।
  - **मिट्टी की नमी (Soil Moisture):** मिट्टी में पानी की मात्रा की जांच।
  - **जल निकायों का स्तर:** जलाशयों और भूजल स्तर में आई गिरावट।
- **जमीनी सत्यापन (Ground Truthing):**
  - राजस्व और कृषि विभाग की टीमें गांवों में जाकर फसलों के नुकसान (Crop Loss) का भौतिक आकलन करती हैं।
  - यदि क्षेत्र में **33% या उससे अधिक फसल का नुकसान** पाया जाता है, तब उस क्षेत्र को आधिकारिक रूप से 'सूखाग्रस्त' (मध्यम या गंभीर श्रेणी) घोषित किया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. सूखा घोषित होने पर किसानों को क्या लाभ मिलते हैं?

Ecology

- फसल मुआवजा एवं वित्तीय सहायता
- ऋण राहत (Loan Relief & Restructuring)
- कृषि इनपुट पर सब्सिडी
- रोजगार और राहत कार्य

महत्वपूर्ण तथ्य

Kasturirangan report on Western Ghats threatens livelihoods: Karnataka CM

The Hindu Bureau
BENGALURU

Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar on Monday told the Legislative Assembly that the proposed implementation of the Kasturirangan Committee report could threaten the livelihoods of people in 10 districts, even as he reaffirmed the State government's commitment to protecting the livelihoods of farmers and residents of the Western Ghats.

During the debate on the report, Mr. Shivakumar said its recommendations had created "an atmosphere of fear" among farmers. "More than six rivers originate and flow through the Western Ghats. The proposal of unscientific measures has caused widespread anxiety regarding people's livelihoods," he said. Before attending the session, Mr. Shivakumar had toured the coastal and Malnad regions, which would be affected by the report, and had held meetings with people.

According to the Kasturirangan report, 20,668 sq. km of Karnataka's Western Ghats region has been identified as ecologically sensitive, covering 1,449 villages. Mr. Shivakumar said people and farmers had made several suggestions during his consultations. "Farmers have sought rejection of the report and have demanded that a new committee be constituted. They have also urged that the Ecologically Sensitive Zone classification be scrapped and the Keralam model adopted," he said.

The Centre has asked Karnataka to convey its decision on the report by September 27.

YouTube Homework

- Fauna & Flora of Western Ghat

महत्वपूर्ण तथ्य

कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट (Kasturiranjan Report)

पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट (2013)

- भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने डॉ. के. कस्तूरीरंगन (पूर्व ISRO प्रमुख) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल (HLWG) का गठन किया था। इसका उद्देश्य गाडगिल समिति (Gadgil Commission) की सिफारिशों का पुनर्मूल्यांकन करना और पर्यावरण संरक्षण व विकास के बीच संतुलन बनाना था।

प्रमुख सिफारिशें और बिंदु:

- **37% क्षेत्र का संरक्षण:** समिति ने पूरे पश्चिमी घाट (लगभग 60,000 वर्ग किमी क्षेत्र) के **37% भाग** को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area - ESA) घोषित करने की सिफारिश की।
- **गतिविधियों पर प्रतिबंध:** ESA घोषित क्षेत्रों में निम्नलिखित पर पूरी तरह रोक लगाने का सुझाव दिया गया:
  - खनन (Mining) और खदान कार्य।
  - थर्मल पावर प्लांट।
  - प्रदूषण फैलाने वाले भारी उद्योग (Red Category Industries)।
  - 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के बड़े भवन और निर्माण परियोजनाएं।

विकास की अनुमति: गाडगिल रिपोर्ट की तुलना में कस्तूरीरंगन रिपोर्ट अधिक व्यावहारिक मानी गई, क्योंकि इसने सतत विकास (Sustainable Development) को ध्यान में रखते हुए सीमित कृषि, जलविद्युत परियोजनाओं (शर्तों के साथ) और बुनियादी ढांचे के निर्माण की अनुमति दी।

स्थानीय विरोध: केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस रिपोर्ट का भारी विरोध हुआ, क्योंकि स्थानीय लोगों और सरकारों को डर था कि इससे कृषि, बगान (Plantations) और लोगों के पुनर्वास पर असर पड़ेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

Aadhaar no proof of age for registration of marriage: Karnataka

The Hindu Bureau
BENGALURU

The Department of Stamps and Registration in Karnataka has directed officials across the State to not consider Aadhaar card as proof of age for the bride and groom for registration of marriages.

In a circular, it said, "Officials must consider either birth certificate or school certificate and in the absence of these two documents, they can consider medical certificate issued by doctor for registration of marriage." The direction came in the light of incidents where the age in the Aadhaar card and birth certificate were mismatched, resulting in child marriage.

Child rights activists across the State have alleged that parents or guardians of the bride changed the age in the Aadhaar card photocopy or through a correction window available under the Unique Identification Authority of India (UIDAI)."

महत्वपूर्ण तथ्य

- आधार कार्ड (Aadhaar Card) भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक 12-अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर (Unique Identification Number) है। यह देश के नागरिकों और निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान और पते का प्रमाण है।

1. आधार कार्ड कब आया?

- **योजना की शुरुआत:** भारत सरकार ने जनवरी 2009 में आधार योजना की रूपरेखा तैयार की थी।
- **पहला आधार कार्ड जारी:** भारत का **पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010** को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के टेंभली गांव की निवासी **रंजना सोनवणे** को जारी किया गया था।

2. इसे कौन बनाता/जारी करता है?

- आधार कार्ड **UIDAI (Unique Identification Authority of India)** यानी **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण** द्वारा जारी किया जाता है।
- UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत काम करने वाली एक वैधानिक प्राधिकरण (Statutory Authority) है, जिसकी स्थापना आधार अधिनियम, 2016 (Aadhaar Act, 2016) के तहत की गई थी।

3. अब तक कितने आधार कार्ड जारी हुए हैं?

- UIDAI के आंकड़ों के अनुसार, भारत में **138 करोड़ से अधिक** आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
- भारत की वयस्क आबादी (Adult Population) का लगभग **99% से अधिक** हिस्सा आधार से कवर हो चुका है।

4. किन-किन चीज़ों में आधार कार्ड अनिवार्य (Mandatory) है?

- सुप्रीम कोर्ट के 2018 के ऐतिहासिक फैसले और सरकारी संशोधनों के बाद आधार कार्ड की अनिवार्यता को स्पष्ट किया गया है:

जहाँ अनिवार्य/ज़रूरी है:

- **PAN कार्ड से लिंक करना:** आयकर (Income Tax) रिटर्न भरने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
- **सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएँ:** 'आधार अधिनियम की धारा 7' के तहत सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी, पेंशन, राशन (PDS), और वित्तीय सहायता (जैसे PM-किसान योजना) प्राप्त करने के लिए आधार mandatory है।
- **EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि):** पीएफ (PF) खाते से निकासी और पेंशन दावों के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण तथ्य

जहाँ अनिवार्य नहीं है (ऐच्छिक / Voluntary):

- **बैंक खाता खोलना:** बैंक में खाता खोलने के लिए आधार देना अनिवार्य नहीं है, यह एक वैकल्पिक (Optional) KYC दस्तावेज़ है।
- **मोबाइल सिम कार्ड (SIM Card):** नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार देना बाध्यकारी नहीं है; आप पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि का उपयोग भी कर सकते हैं।
- **स्कूल/कॉलेज में एडमिशन:** बच्चों के एडमिशन या बोर्ड परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं किया जा सकता।
- **सफर व निजी सेवाएँ:** प्राइवेट कंपनियों, होटल चेकिन या हवाई/रेल यात्रा के लिए आधार देना अनिवार्य नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य

Will try to list Mamata's plea against EC decision to freeze symbol of Trinamool: CJI

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Supreme Court on Monday agreed to try and list a petition filed by former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee against a decision by the Election Commission to freeze the symbol of the Trinamool Congress.

Appearing before Chief Justice of India Surya Kant, who is leading a three-judge Bench, senior advocate Kapil Sibal, representing Ms. Banerjee, made an oral mentioning that the Election Commission's interim order freezing the symbol, even as proceedings under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order 1968, was unwarranted.

"The Election Commission is crossing new milestones every time," Mr. Sibal submitted.

Mamata Banerjee

Chief Justice Kant said both sides would have arguments to make, and the court would hear all the parties. "We will try to hear it this week," he said.

New allotment

The petition was filed hours after the poll body, on September 17, allotted new names and symbols to the two factions of the Trinamool led by Mamata and Ritabrata Banerjee.

The Mamata faction got the name "Mamata All India Trinamool Congress" with "football player" as its symbol, while the Ritabrata grouping was allotted the name "Democratic Trinamool Congress" with the symbol "envelope".

The plea said the EC did not comprehensively look into the party structure while considering rival claims made by the camps. The petition said the EC had banked on the statements of rebel legislators.

The Mamata camp has filed a petition highlighting the delay in the disqualification proceedings pending before the West Bengal Assembly Speaker against the 10 legislators from the rebel faction.

YouTube Homework

- Anti Defection Law

महत्वपूर्ण तथ्य

- चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 [Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968] भारत में चुनाव चिन्हों के आवंटन और राजनीतिक दलों के पंजीकरण को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है।
- इसे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा **अनुच्छेद 324** और **चुनाव संचालन नियम**, 1961 (Conduct of Elections Rules, 1961) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके जारी किया गया था।
- इस आदेश के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. राजनीतिक दलों का वर्गीकरण (Classification of Parties)

- इस आदेश के तहत भारत के सभी राजनीतिक दलों को तीन वर्गों में बांटा गया है:
- **राष्ट्रीय दल (National Parties):** इन्हें एक स्थाई चुनाव चिन्ह मिलता है, जो पूरे देश में इन्हीं के लिए आरक्षित (Reserved) रहता है।
- **राज्य स्तरीय दल (State Parties):** इन्हें उस विशिष्ट राज्य में एक स्थाई चुनाव चिन्ह मिलता है जहाँ ये मान्यता प्राप्त हैं।
- **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल (Registered Unrecognized Parties):** इनके पास कोई आरक्षित चुनाव चिन्ह नहीं होता। इन्हें चुनाव आयोग की 'मुफ्त प्रतीकों' (Free Symbols) की सूची में से चुनाव चिन्ह चुनना पड़ता है।

2. चुनाव चिन्हों का वर्गीकरण

- चुनाव चिन्हों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:
- **आरक्षित प्रतीक (Reserved Symbols):** ये केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होते हैं।
- **मुक्त प्रतीक (Free Symbols):** यह उन चुनाव चिन्हों की एक सूची होती है जो किसी दल के लिए आरक्षित नहीं हैं। इन्हें निर्दलीय (Independent) उम्मीदवारों और गैर-मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों को आवंटित किया जाता है।

3. पार्टी में विभाजन या विलय पर निर्णय (पैराग्राफ 15)

- इस आदेश का **पैराग्राफ 15 (Paragraph 15)** सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण भाग है:
- जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में विभाजन (Split) होता है और दो या दो से अधिक गुट 'असली पार्टी' होने का दावा करते हैं, तो निर्वाचन आयोग इसी पैराग्राफ 15 के तहत फैसला सुनाता है।
- आयोग पार्टी के संगठनात्मक ढांचे (Organizational Wing) और विधायी ढांचे (Legislative Wing - सांसद/विधायक) में बहुमत का परीक्षण करके असली पार्टी और चुनाव चिन्ह का निर्धारण करता है।
- यदि स्थिति स्पष्ट न हो या मामला जटिल हो, तो आयोग चुनाव चिन्ह को **फ्रीज (जब्त)** भी कर सकता है और दोनों गुटों को नए नाम व नए 'फ्री सिंबल' आवंटित कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

4. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल का दर्जा देने के मानदंड

- इस आदेश में विशिष्ट शर्तें दी गई हैं जिनके आधार पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलता है:
- **राज्य स्तरीय दल (State Party):** राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट और 2 सीटें, या कुल सीटों का 3% प्राप्त करना (अन्य शर्तों में से एक)।
- **राष्ट्रीय दल (National Party):** कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होना, या लोकसभा में कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से 2% सीटें जीतना।

महत्वपूर्ण तथ्य

Unsafe space

Deployment of weapons calls for multilateral governance in space

Although the U.S. military doctrine was openly considering offensive and defensive space control by 2025, the admission on September 14 by U.S. Air Force Secretary Troy Meink, and confirmed by Space Force chief Gen. Douglas Schiess, that the country has deployed "on-orbit space control weapons" to "defend against hostile adversary action" is cause for concern. Satellite systems increasingly underpin communications, energy, and financial networks and many commercial systems serve civilian and military users. To that end, the U.S., Russia, China, and India, among others, have been developing counter-space capabilities while contributing to the technological and strategic environment rendering earth orbit the next major battlefield. The increasing military use of commercial satellites can endanger the protections they enjoy under international humanitarian law even as this law is underprepared for satellites being highly interconnected and often dual-use. That said, the details that justify the need for orbital defence systems also make poorly specified weapons a potential cause of instability. Mr. Meink described the weapon as defensive, but U.S. military doctrine defines "space control" as encompassing both offensive and defensive operations.

Compounding the consequences of confusion when two steerable satellites approach each other without understanding the other's intentions – including due to future autonomous satellites running artificial intelligence models onboard – is the lack of policy details. What constitutes "hostile action" and what the weapon can do remain unclear. While the Outer Space Treaty does not ban weapons in orbit *per se*, Article IV prohibits nuclear weapons or other weapons of mass destruction in orbit – a fluid line considering the centrality of satellite-based networks for contemporary society and the ability of conventional weapons to render damage en masse; its Article III also requires space activities to comply with international law. But when an autonomous, dual-use orbital asset operated by a commercial entity initiates an unwanted defensive strike, the existing rules, including the Liability Convention, cannot be applied straightforwardly to determine accountability. The rules have become too coarse for what contemporary technologies, and the declining esteem for a rules-based world order, warrant. The U.N. Open-Ended Working Group on the 'Prevention of an Arms Race in Outer Space' should offer governments an opportunity to address the disclosure. The U.S. government should also reveal the particulars of the weapons it has deployed, and enter into a multilateral governance arrangement that defines exact thresholds of action and escalation.

महत्वपूर्ण तथ्य

अंतरिक्ष में हथियार तैनात

1. हालिया घोषणा और मुख्य बिंदु (Main Disclosure)

- **आधिकारिक पुष्टि:** 14 सितंबर 2026 को अमेरिकी वायु सेना सचिव (US Air Force Secretary) ट्रॉय मींक और **US Space Force** ने सार्वजनिक रूप से पहली बार स्वीकार किया कि अमरीका ने कक्षा (Orbit) में **"स्पेस कंट्रोल वैपन्स" (Space Control Weapons)** तैनात कर दिए हैं।
- **उद्देश्य:** अमरीकी रक्षा पेंटागन के अनुसार, इन हथियारों को दुश्मन देशों (विशेषकर रूस और चीन) के संभावित खतरों और अपनी सैन्य संपत्तियों/उपग्रहों (Satellites) की सुरक्षा के लिए ऑर्बिट में स्थापित किया गया है।
- **गोपनीयता:** अमरीकी सेना ने सुरक्षा कारणों से यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये हथियार किस प्रकार के (Kinetic/Non-kinetic) हैं, लेकिन यह पहली बार है जब अमरीका ने अंतरिक्ष में ऑन-ऑर्बिट हथियारों की मौजूदगी को स्वीकार किया है।

2. 'गोल्डन डोम' (Golden Dome) कार्यक्रम

- इसके अलावा, अमरीकी रक्षा विभाग ने अपने नए रक्षा कार्यक्रम **"गोल्डन डोम" (Golden Dome Missile Defense Shield)** पर तेजी से काम शुरू किया है:
- इसका लक्ष्य अंतरिक्ष में हजारों छोटे उपग्रहों (Constellations) का ऐसा नेटवर्क स्थापित करना है जो दुश्मन देश की **हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके उड़ान भरते ही (Space-based Interceptors)** अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सके।
- पेंटागन ने इसके परीक्षण 2026-2027 में शुरू करने की समय-सीमा तय की है।

3. अमरीका ने यह कदम क्यों उठाया?

- **रूस और चीन से सीधा मुकाबला:** अमरीका का दावा है कि चीन और रूस लगातार **एंटी-सैटेलाइट (ASAT)** हथियार, लेजर और जैमिंग तकनीकों का परीक्षण कर रहे हैं, जिससे उसके सैन्य और नागरिक जीपीएस (GPS) को खतरा है।
- **अंतरिक्ष-आधारित परमाणु खतरा:** रूस द्वारा अंतरिक्ष में एंटी-सैटेलाइट क्षमता वाले परमाणु उपकरण विकसित करने की खबरों के बाद अमरीका ने अपने स्पेस डिफेंस सिस्टम को और आक्रामक बना दिया है।
- **आधुनिक युद्ध की निर्भरता:** आज की युद्धप्रणाली (Warfare) पूरी तरह उपग्रह डेटा पर निर्भर है; इसलिए अमरीका अंतरिक्ष के "वर्चस्व" (Dominance) को खोना नहीं चाहता।

महत्वपूर्ण तथ्य

4. कानूनी पहलू (Outer Space Treaty, 1967)

- **1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी:** यह अंतर्राष्ट्रीय संधि अंतरिक्ष में **परमाणु हथियार (Nuclear Weapons) या सामूहिक विनाश के हथियार (WMD)** तैनात करने पर सख्त प्रतिबंध लगाती है।
- **कानूनी ढील (Loophole):** यह संधि लेजर तकनीक, जैमिंग या काइनेटिक मिसाइलों जैसे **पारंपरिक (Conventional) हथियारों** पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगाती, जिसका फायदा उठाकर यह तैनाती की जा रही है।

5. वैश्विक चिंताएं (Global Impact)

- **नया अंतरिक्ष हथियार दौड़ (Space Arms Race):** अमरीका की आधिकारिक पुष्टि के बाद रूस, चीन और अन्य प्रमुख देश भी अपने ऑर्बिटल हथियार तैनात करने में तेजी लाएंगे।
- **स्पेस देबरिस / कचरा (Space Debris):** अंतरिक्ष में किसी उपग्रह या मिसाइल के टकराने से लाखों छोटे टुकड़े पैदा होंगे, जो अन्य वैज्ञानिक, मौसम और व्यावसायिक उपग्रहों (जैसे ISS) को नष्ट कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

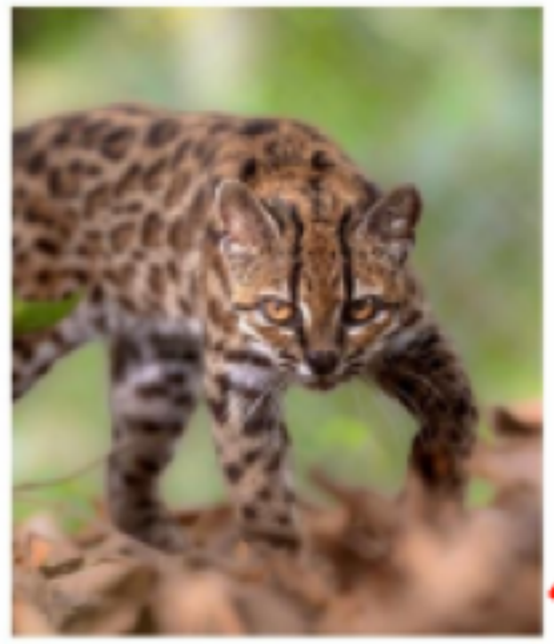

The Tilcayo measures about 46 cm long and weighs around 1.4 kg, making it smaller than the average domestic cat. REUTERS

Cat family gets a new Bolivian member after over a century

Reuters

A diminutive wild cat that inhabits Bolivia's cloud forest has been identified as a previously unknown species, marking the first time a new living cat species has been formally named and described in more than a century.

The cat, called Tilcayo by local communities, is part of a group called tiger cats found across much of South America. It was found in Bolivia's lush Yungas forest, a mountainous region where forests are often covered by clouds and surrounded by high humidity, according to researchers. It measures about 46 cm long and weighs around 1.4 kg, making it smaller than the average domestic cat.

Researchers used genetic data to confirm that the cat is a new species, and gave it the scientific name *Leopardus tilcayo*, retaining its local name. "Its fur is light brown ... with irregularly shaped rosettes across its body," said Paola Nogales-Ascarrunz, a National Geographic explorer and one of the authors of the study describing the newly identified

Researchers used genetic data to confirm that the cat is a new species, and gave it the scientific name *Leopardus tilcayo*

species published on September 17 in the journal *Current Biology*. Little is yet known about the cat's biology and lifestyle. Remains of small rodents in scat samples suggest they may form part of its diet, while camera-trap evidence indicates it could be more active at night, Ms. Nogales-Ascarrunz said.

Tiger cats are so-called cryptic species, meaning they cannot easily be distinguished merely by appearance, said evolutionary biologist and study co-lead author Jonas Lescroart of the University of Antwerp in Belgium. Tiger cats previously had been considered a single species, but genetic studies decades ago suggested the existence of multiple species. Referring to the new species, Mr. Lescroart said, "Our information at this moment is limited to the two live individuals that we examined, and a small number of camera-trap records."

One of the live cats is a 10-year-old male that now lives in Senda Verde Wildlife Sanctuary after being kept by a local family in their home. Observing the Bolivian cat drew interest because "its characteristics did not match the descriptions, most of them based on Brazilian cats," Ms. Nogales-Ascarrunz said. "This made us wonder: what tiger cat do we actually have in Bolivia?"

The team analysed DNA from 38 cats sampled across several South American countries, including eight museum specimens. The study found that tiger cats are in fact five genetically distinct species.

"We never expected this Bolivian tiger cat to be a separate species, and no one had ever proposed it as a different animal, subspecies or otherwise," Mr. Lescroart said. Genetic analysis suggested that the Tilcayo lineage separated from other tiger cats about 1.4 million years ago. "The more differences in their DNA, the longer the time that we estimate those lineages to have been physically separated," Mr. Lescroart said, adding that such a gap is generally considered a species-level divide in cats.

The research team also described a new tiger cat subspecies in Peru's Yungas, naming it *Leopardus tigrinus antisuyo* after Antisuyu, the region of the old Inca Empire that included the area it inhabits.

The International Union for Conservation of Nature, or IUCN, Red List tracking the status of species currently treats tiger cats as two "vulnerable" species with declining populations.

महत्वपूर्ण तथ्य

बिल्ली के परिवार (Cat Family) में शामिल हुई एक नई जंगली बिल्ली की प्रजाति

- 100 से भी अधिक वर्षों में पहली बार दक्षिण अमेरिका में बिल्ली की किसी नई जीवित प्रजाति का औपचारिक रूप से नामकरण और वर्णन किया गया है।
- इस खोज के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. प्रजाति का नाम और आकार

- **स्थानीय व वैज्ञानिक नाम:** स्थानीय समुदाय इसे **'टिल्कायो' (Tilcayo)** कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका वैज्ञानिक नाम **'लियोपार्डस टिल्कायो' (*Leopardus tilcayo*)** रखा है।
- **आकार:** यह एक बहुत ही छोटे आकार की जंगली बिल्ली है। इसकी लंबाई लगभग **46 सेमी** और वजन लगभग **1.4 किग्रा** है, जो इसे एक सामान्य घरेलू बिल्ली से भी छोटा बनाता है।
- **शारीरिक बनावट:** इसका फर हल्का भूरा है और इसके शरीर पर अनियमित आकार के रोसेट (Rosettes/धब्बे) बने हुए हैं।

2. आवास और व्यवहार (Habitat & Behavior)

- **स्थान:** यह बोलीविया के पहाडी क्षेत्र **युंगास (Yungas)** के घने जंगलों में पाई गई है, जहाँ अक्सर धुंध/बादल और उच्च आर्द्रता (Humidity) रहती है।
- **खान-पान व दिनचर्या:** मल के नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि इसके आहार में छोटे कुतरने वाले जीव (Rodents) शामिल हैं। कैमरा-ट्रैप साक्ष्यों के अनुसार यह मुख्य रूप से रात में अधिक सक्रिय होती है।

3. वैज्ञानिक प्रमाण और आनुवंशिक खोज (Genetic Discovery)

- वैज्ञानिकों ने **डीएनए (DNA) डेटा** के जरिए यह साबित किया कि यह टाइगर कैट (Tiger Cat) की एक बिल्कुल अलग प्रजाति है।
- आनुवंशिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि टिल्कायो की वंशावली लगभग **1.4 मिलियन (14 लाख) वर्ष पहले** अन्य टाइगर कैट प्रजातियों से अलग हो गई थी।
- इस अध्ययन से यह भी सामने आया कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली टाइगर कैट्स वास्तव में 5 आनुवंशिक रूप से अलग-अलग प्रजातियाँ हैं।
- यह शोध पत्र 12 सितंबर को जर्नल *Current Biology* में प्रकाशित हुआ है।

4. संरक्षण की स्थिति (Conservation Status)

- IUCN (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर) की रेड लिस्ट में टाइगर कैट्स को वर्तमान में **'सुभेद्य' (Vulnerable)** श्रेणी में रखा गया है, जिनकी आबादी लगातार घट रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

भारत में कोयला से बिजली उत्पादित करने वाले संयंत्र कितने ??

'Nearly 40% of coal power plants critically low on fuel'

The number of power plants with critically low coal stocks of less than 25% of the required inventory rose sharply to 74 as of September 19 from about 60 plants last week, data show

Reuters
NEW DELHI

Nearly 40% of India's coal-fired power plants are operating with critically low fuel stocks due to a surge in power demand amid hotter-than-usual weather linked to El Niño, government data showed on Monday.

The number of power plants with critically low coal stocks of less than 25% of the required inventory or only able to generate power for less than three days rose sharply to 74 as of September 19 from about 60 plants last week, data from the Central Electricity Authority that is updated daily showed.

Power struggle: India's peak power demand has been hovering between 230 gigawatts and 250 gigawatts in the past week. REUTERS

India's peak power demand, a measure of the maximum electricity requirement, has been hovering between 230 gigawatts and 250 gigawatts in the past week.

Peak power demand hit an all-time high of 270.70 gigawatts in May.

The decline in power plant stocks appears to be a temporary logistical issue rather than a sign of any structural supply constraints, Crisil analysts said. India's coal and railway ministries said in early September they were increasing supplies to the plants after erratic monsoon rains had impacted shipments.

Renewable power generation rose about 21% between April and August, but due to the intermittent nature of clean energy, coal-fired power continued to play a critical role in meeting round-the-clock demand, Crisil said.

Meanwhile, Indian power producers' coal imports in August rose to a 15-month high as a heatwave boosted electricity demand while hydroelectric power generation remained subdued, prompting utilities to turn to costly overseas supplies, *Reuters* reported last week.

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

UPI heads towards a code-less era, a decade after debut

Ashokamithran T.
MUMBAI

A decade after the launch of the Unified Payments Interface (UPI), payment companies are moving towards a new phase of digital payments that seeks to make transactions faster and do away with one-time passwords (OTPs) and QR codes.

The Reserve Bank of India (RBI) Governor last week launched a 'tap and pay' facility for UPI transactions in partnership with the National Payments Corporation of India (NPCI), enabling payments through RuPay credit cards without the need for OTPs or QR codes.

The facility was unveiled at the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai.

The new feature uses the point-of-sale (PoS) terminal's internet connectivity, allowing a transaction to be completed even when the customer's mobile device does not have internet access. NPCI said the facility is currently available for transactions of up to ₹5,000. For higher-value transactions, customers will have to enter their PIN.

UPI has emerged as India's dominant electronic payment system, accounting for about 85% of transactions. Introduced in the aftermath of demonetisation, its rapid adoption has been driven largely by the convenience of making retail and utility payments without the need for cash.

However, the growing

QR code is going to be a thing of the past.

scale of digital payments has also brought heightened concerns over fraud, including incidents involving the theft or inadvertent sharing of OTPs and other authentication credentials.

In response, the RBI mandated a two-factor authentication for UPI transactions from April 1, 2026, prompting payment companies to develop alternatives that combine security with ease of use.

Visa and Mastercard, for instance, have introduced passkeys as an additional authentication mechanism. Mastercard has also showcased its Consumer Device Cardholder Verification Method (CDCVM), which allows transactions to be authenticated through a device's biometric capabilities, including fingerprint or facial recognition. Mastercard has partnered with Google Pay to offer the service.

Amazon Pay, which accounts for less than 1% of UPI transactions, has also introduced a tap-and-pay facility for its partner merchants as it seeks to expand its presence in the digital payments market.

Global Fintech Fest -2026
Mumbai

- Payment & Settlement Act -2007
- NPCI
- UPI
- MDR

महत्वपूर्ण तथ्य

India to attend session on UN-based multilateralism

U.N.

→ UNGA

संयुक्त राष्ट्र महासभा 80वें सत्र का आयोजन

EU, Brazil, Kenya, Canada launch grouping beyond 'superpower politics'; the P4M initiative seeks a more representative UN that is prepared for global challenges, including AI and climate change

Suhasini Haidar
NEW DELHI

India will join a number of countries committed to supporting United Nations (UN)-based multilateralism, away from "Superpower" politics, as External Affairs Minister S. Jaishankar was set to attend the "Partners for Multilateralism" (P4M) meeting at the United Nations.

Mr. Jaishankar landed in New York on Monday at the start of the UN General Assembly's "High-Level debate" session. He is due to hold a number of bilateral meetings and multilateral meetings there, and will address the UNGA on September 26.

Gearing up: Security guards checking IDs of people ahead of the United Nations General Assembly in New York. REUTERS

The P4M initiative, founded by leaders of the European Union, Brazil, Kenya and Canada is expected to make a pitch for the grouping this week.

In a joint editorial, leaders of the four founders said the grouping will support the UN but push for it to be more representative and prepared for global challenges, including AI (artificial intelligence), climate change, health security and digital transformation.

"P4M will support the reform of the UN and other multilateral institutions, to make them more representative, legitimate, effective and trusted," the leaders, including European Council President Antonio Costa, Brazil President Lula da Silva, Kenyan President William Rutto and Canadian Prime Minister Mark Carney wrote in an editorial published in the U.K.-based *Financial Times*.

Mr. Carney had delivered a speech on "Middle powers" coming together at the World Economic Forum in Davos in January, which signalled growing dissatisfaction not just with Russia and China for unilateral moves and conflicts, but with the United States over trade and tariffs, expansionist moves, and the conflict in Iran that have been undertaken during U.S. President Donald Trump's second term.

It is unclear whether India was asked to join the joint message.

India is already part of a number of groups like the Non-Aligned Movement, BRICS, G20, and G-4 that have similar objectives.

India is already part of a number of groups like BRICS and G20 that have similar objectives

The editorial on Monday pointed to comments by United Nations Secretary-General António Guterres in which he had said that "superpowers are discovering their limits", adding that the P4M grouping believes that the "international community must rediscover the extraordinary potential of collective action".

Mr. Guterres, who demits office later this year, spoke to *The Hindu* amongst five global outlets in U.S., U.K., South Africa, the Gulf region and India.

"We have superpowers that have not yet recognised that their power has limits and they get into adventures that produce terrible results," Mr. Guterres had said, specifically pointing to Russia, which was still embroiled in the war in Ukraine four years later, while the U.S. is facing "difficulties" with its war in Iran.

'Limits to powers'

"I think it's time for superpowers to understand the limits of their power, and that will help the world become more peaceful," Mr. Guterres said, speaking to *The Hindu* in New Delhi, where he attended the 18th BRICS Summit.

The editorial also said that the 'Partners for Multilateralism', would not create another exclusive bloc or international bureaucracy.

"Its purpose is the opposite: to create a flexible, open framework for countries from different regions and political traditions that are willing to work across divides, to build coalitions for reform and to translate shared principles into practical action," the co-authors wrote, pointing out that 2025 saw the highest recorded number of state-based armed conflicts since 1946, in 35 countries, and highest recorded military spending of nearly $3 trillion.

महत्वपूर्ण तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के **81वें सत्र (UNGA 81st Session)** का विवरण निम्नलिखित है:
- **स्थान (Venue):** संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (UN Headquarters), न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)।
- **तिथि / अवधि (Dates):**
  - महासभा सत्र का औपचारिक शुभारंभ: **8 सितंबर 2026**।
  - उच्च-स्तरीय सामान्य बहस (High-Level General Debate): **22 सितंबर से 28 सितंबर 2026**।
  - यह सत्र पूरे एक वर्ष तक (सितंबर 2027 तक) चलेगा।
- **अध्यक्ष (President/Chairman):** **खलीलुर रहमान (Khalilur Rahman)**। वे बांग्लादेश के विदेश मंत्री और अनुभवी राजनयिक हैं।
- **मुख्य विषय (Theme): "Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All"** *(विश्वास की पुनर्बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन: एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए परिणाम दे)*।

- **Partners for Multilateralism (P4M) – *अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति (International Relations)***
- हाल ही में (21 सितंबर 2026 को UN General Assembly के 81वें सत्र के दौरान) विभिन्न देशों के नेताओं ने **P4M (Partners for Multilateralism)** नाम से एक नई वैश्विक पहल की शुरुआत की है।
- **उद्देश्य:** इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय कानून, शांति, जलवायु परिवर्तन, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और व्यापार में बहुपक्षवाद (Multilateralism) को मजबूत करना है।
- **प्रमुख नेता:** इस पहल में कनाडा, ब्राजील, केन्या, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय परिषद के राष्ट्राध्यक्ष व प्रधानमंत्री शामिल हैं।
- **स्वरूप:** यह कोई नया प्रशासनिक ढांचा (bureaucratic block) नहीं है, बल्कि UN और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों को समर्थन देने के लिए एक खुला और लचीला नेटवर्क है।

महत्वपूर्ण तथ्य

YT-HW
↳ Asian Games

Himanshu comes of age as marksmen get going

The youngster pips senior pro Rudrankksh to silver in 10m air rifle in a dramatic final; the two, along with Parth, also bag a silver in the team event; China's Sheng retains his individual title

ASIAN GAMES

Uthra Ganesan
NAGOYA

Doing the country proud: Himanshu and Rudrankksh ensured a double podium finish for India.
R.V. MOORTHY

Impressive outing: Himanshu, Rudrankksh and Parth finished second behind China in the team event.
R.V. MOORTHY

India's wait for its first gold from the Aichi-Nagoya Asian Games continued on the second day even as the shooters added three more medals to the tally, including double podium finish in the 10m air rifle, here on Monday.

Himanshu Dhillon proved he was ready for the big stage, winning his maiden international individual medal at the senior level, pipping Rudrankksh Patil to a silver in a nail-biting, dramatic final that saw defending champion Sheng Lihao retain his title. The two, together with Parth Mane, also won silver as a team. India had won gold in the team event last time around with Rudrankksh the only constant. Himanshu, a week away from his 21st birthday, played a steady hand all through, staying in the top-three at all times with no signs of being a debutant in the spotlight even as senior pro Rudrankksh and Sheng kept exchanging the lead at the top. Till the 15th shot, in fact, Rudrankksh was comfortably in the lead before Sheng crawled back even as Himanshu consolidated his spot. By the 17th shot, the potential medallists had been clearly identified with only the colour of the metal to be decided. A 9.9 on the 18th by Himanshu sent the sizeable Indian presence in the stands into a tense silence before the youngster fought back with a couple of 10.5s.

It was on the 21st shot that the equations turned. Himanshu managed an impressive 10.6 while Rudrankksh, in second position, could only manage a 9.7. It was the lowest score he had shot the whole day and it came at the worst possible time. It helped Himanshu leapfrog into second spot and even though the former found a 10.6 on his final shot, he fell agonisingly short by 0.1 points to finish third.

It was clear at that point that Sheng would walk away with the gold – he had built a two-point difference with two shots to go over Himanshu. But to the youngster's credit, he didn't give up. His final two shots were 10.8 and 10.9, as close to perfection as possible, but Sheng matched up for a new Games and Asian record of 254.2 points, bettering his own previously set mark of 253.3.

Earlier in the qualification, the Indian trio combined for a total of 1,890.1 points while Sheng, along with Ma Sihan and Zhang Changhog, totalled 1899 for China for a new World record, shadowing India's 1,893 three years earlier.

Home Assignment

अगस्त 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अपने 'द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी समझौते' (BEPA) के अगले चरण के लिए वार्ता पूरी की?

BEPA

(A) नेपाल

(B) श्रीलंका

(C) बांग्लादेश

(D) भूटान

Overview

- India-New Zealand FTA
- Arrest and Detention – 22(1)
- Drought in Maharashtra
- Kasturiranjan Report
- Aadhar Card
- TMC Issue
- Weapons in Space
- New Cat – Bolivia – Tilcayo
- Coal Plants / UPI
- UNGA Session 81
- Asian Games

Thank You

Result Mitra

Thanks For
Watching
Follow us for more Updates
Learn
Share
Grow
Together
Better
Students
Brighter
Tomorrow
@RRESULTMITRAOFFICIAL
Join our Telegram
@SUNILVERMA_THEIASMENTOR
Follow on Instagram
Subscribe Now
DISCIPLINE
CONSISTENCY
SUCCESS
Small
Steps
Big
Results
Stay Connected